Authority in October, 1990. The proposal could be techno-economically appraised by the Central Electricity Authority only after all the essential inputs, such as water availability, associated transmission system, etc. are tied up and necessary clearances, including clearance from the environmental angle are obtained by the State Authorities.

राजस्थान में विद्युत परियोजनाएं

676. डा० अबरार अहमद : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में ऊर्जा की कितनी खपत है और इसमें से कितनी ऊर्जा का उत्पादन वहीं पर हो रहा है ;

(ख) राजस्थान में शीघ्र ही प्रारम्भ किये जाने वाले विद्युत संयंत्रों के नाम क्या हैं; और

(ग) राजस्थान की उन विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं जो केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं और इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकने : (क) जनवरी, 1991 के दौरान राजस्थान में ऊर्जा की कुल आवश्यकता 12100 लाख यूनिट थी जबकि सभी स्रोतों से उपलब्धता 11329.02 लाख यूनिट थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े लाख यूनिट में)

(1)	स्वयं का विद्युत उत्पादन	2793.09
(2)	केन्द्रीय क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं से प्राप्ति	7882.00
(3)	अन्य राज्यों से प्राप्ति	653.93
	जोड़	11329.02

(ख) सूरतगढ़ (2×2 मे०वा०) और मंगरोल (3×2 मेगावाट) जल-विद्युत परियोजनाओं को चालू वर्ष के दौरान चालू किये जाने की सम्भावना है।

(ग) राज्य क्षेत्र की स्कीमों का ब्यौरा विरण में दिया गया है।

विवरण

क्र०सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
ताप विद्युत				
1	सूरतगढ़ चरण-I	2×250=500	1253.3	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्कीम तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से ठीक पायी गयी है बशर्ते कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागर विमानन विभाग से स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जाएं तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सम्बद्ध संचरण प्रणाली की स्वीकृति दे दी जाए।

1	2	3	4	5
2	धौलपुर	2×210=420	759.3	राज्य सरकार द्वारा एक नये परियोजना स्थल का पता लगाया गया है जो पर्यावरणीय मानदंडों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। यदि यह स्थल पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया तो इस स्कीम को 250 मेगा० यूनिट संरूपण के साथ संशोधित करने की आवश्यकता होगी।
3	चित्तौड़गढ़ मंडलगढ़	2×210=420 3×210=630	451.8 554.7	जल एवं अन्य निवेश सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा (रा०रा०बि०बो०) और जांच कार्य किए जाने हैं। रा०रा० बि०बो० को जुलाई 1989 में चित्तौड़गढ़ एवं मंडलगढ़ के बीच एक बड़ा ताप विद्युत केन्द्र अवस्थित किए जाने की व्यवहार्यता की जांच करने की भी सलाह दी गयी थी ताकि बेराच नदी से उपलब्ध जल का उपयोग किया जा सके। इन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति भी रा०रा० बि०बो० द्वारा प्राप्त की जानी है।
जल विद्युत				
1	रहूघाट	4×40=160	415.0	मध्य प्रदेश के साथ अंतराज्यीय पहलुओं का समाधान किए जाने के बाद रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत करने हेतु फरवरी 1988 में परियोजना प्राधिकारियों को लौटा दी गई थी। जुलाई 1990 में संशोधित रिपोर्ट शीघ्र भेजने के लिए परियोजना प्राधिकारियों को याद दिलाया गया था।
2	जोलाम संशोधित	1×5.5=5.5	8.00	रिपोर्ट नवम्बर 1988 में परियोजना प्राधिकारियों को लौटा दी गयी थी। यूनिट के आकार, यूनिटों की संख्या, व्यस्ततमकालीन मांग एवं लागत अनुमानों आदि की समीक्षा करने के बाद संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नवम्बर 1989 में परियोजना प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया था।

1	2	3	4	5
3	जावई	2×0.6 +2×0.6=2.4	6.00	विद्युत संबंधी लाभों के मूल्यांकन के लिए सिक्काई विभाग द्वारा स्वीकृत किए अनुसार वास्तविक स्वीकृतियां प्रस्तुत करने के लिए राज्य प्राधिकारियों से कहा गया था । रिपोर्ट नवम्बर, 1988 में लौटाई गई थी ।
4	माउंट आबू बहुद्देशीय परियोजना	2×5=10	16.00	बहुद्देशीय परियोजना होने के कारण स्कीम के विद्युत संबंधी भाग पर के०वि०प्रा० द्वारा केवल तभी ही विचार किया जा सकता है जब कि परियोजना को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत कर दिया जाय । पैनस्टाक एवं अन्य सिविल संरचनाओं की लंबाई कम करने के लिए वैकल्पिक विद्युत घर स्थल पर विचार करने की सलाह परियोजना प्राधिकारियों को दी गई थी । अप्रैल, 1990 में परियोजना प्राधिकारियों से संशोधित रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए याद दिलाया गया था ।
5	कोटा पम्पड स्टोरेज	2×100=200	158.00	आगे और जांच कार्यों एवं विकल्पों की जांच करने के बाद रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत करने के लिए अक्तूबर, 1989 में लौटा दी गई थी । रा०रा०वि० बोर्ड द्वारा स्कीम को छोड़ दिया गया है ।

Taking over of Vishwayatan Yogashram

677. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for take over of Dhirendhra Brahmachari's Vishwayatan Yogashram in Delhi; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI DASAI CHOWDHARY): (a) and (b) A proposal for taking over the management of Vishwayatan Yogashram alongwith Central Research Institute for Yoga is receiving active consideration of the Government in the Ministry of Health & Family Welfare in consultation with other concerned Ministries.